सरदारशहर सीट पर उपचुनाव गहलोत... 7

सांध्य दैनिक 4PM

जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_Sanjay YouTube @4pm NEWS NETWORK

● वर्षः 8 ● अंकः 245 ● पृष्ठः 8 ● लखनऊ, शनिवार, 15 अक्टूबर, 2022

मूल्य ₹ 3/-

अपनी बेटियों का सम्मान करिए। वे सम्माननीय हैं।
–मलाला युसुफजई

यूपी में पूरे दमखम से निकाय चुनाव... 3

अफसरों के कामकाज से खुश नहीं... 2

कानून मंत्रियों के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, न्याय मिलने में देरी बड़ी चुनौती

- नागरिकों को समझने में कानून की भाषा न बने बाधक
- लोक अदालतों से न्यायालयों का बोझ हुआ कम
- डेढ़ हजार से ज्यादा अप्रासंगिक कानूनों को किया खत्म

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून मंत्रियों के सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा, स्वस्थ समाज के लिए मजबूत न्यायपालिका का होना जरूरी है। ऐसे में जरूरी है कि कानून बनाते हुए हमारा फोकस ऐसा हो कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ सके। किसी भी नागरिक के लिए कानून की भाषा बाधा न बने, हर राज्य इसके लिए भी काम करें। इसके लिए लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट भी चाहिए। उन्होंने न्याय मिलने में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय मिलने में देरी देश के लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।

कुरीतियों को हटा रहा समाज

प्रधानमंत्री ने कहा, आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तब लोकहित को लेकर सरदार पटेल की प्रेरणा हमें सही दिशा की ओर ले जाएगी। यह हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगी। भारतीय समाज की विकास यात्रा हजारों वर्षों पुरानी है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भारतीय समाज ने निरंतर प्रगति की है। हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह प्रगति के पथ पर बढ़ते हुए खुद में आंतरिक सुधार भी करता चलता है। हमारा समाज अप्रासंगिक हो चुके कायदे-कानूनों, कुरीतियों और गलत रिवाजों को हटाता भी चलता है।

सीएसआईआर बैठक की अध्यक्षता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानून मंत्रियों को संबोधित करने के बाद वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) सोसायटी की बैठक में पहुंचे। उन्होंने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।

उन्होंने कहा, देश के लोगों को सरकार का अभाव नहीं लगना चाहिए और न देशवासियों को सरकार का दबाव महसूस होना चाहिए इसलिए सरकार ने डेढ़ हजार से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे थे। उन्होंने लोक अदालतों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन अदालतों ने लाखों मामलों को सुलझाया है। इनसे न्यायालयों का बोझ कम हुआ है और गांव में रहने वाले लोगों को, गरीबों को न्याय मिलना भी बहुत आसान हुआ है। उन्होंने कहा, टेक्नोलॉजी किस तरह से आज न्याय व्यवस्था का भी अभिन्न अंग बन गई है, इसे हमने कोरोना काल में देखा है। आज देश में ई-कोर्ट्स मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है।

दिवाली के पहले महंगाई का एक और झटका, दूध के दाम बढ़े

- अमूल का फुल क्रीम मिल्क अब मिलेगा 63 रुपये लीटर
- मदर डेयरी भी नई कीमतों का कर सकती है ऐलान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिवाली से पहले आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। भारत की नामी डेयरी कंपनी अमूल ने फुल क्रीम और भैंस के दूध की कीमत में दो रुपये का इजाफा किया है।

अमूल का अब फुल क्रीम दूध 61 की जगह 63 रुपये प्रतिलीटर के हिसाब से मिलेगा। वहीं अब मदर डेयरी भी कीमत बढ़ाने की तैयारी में है। मदर डेयरी जल्द नई कीमत की घोषणा कर सकती है। अमूल के फुल क्रीम मिल्क की बढ़ी कीमत को लेकर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के एमडी आरएस सोढ़ी ने कहा है कि अमूल ने गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों में फुल क्रीम दूध और भैंस के दूध की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। वहीं पंजाब में डेयरी कंपनी वेरका ने भी दूध के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। आधा किलो के पैकेट में एक रुपये की बढ़ोतरी की गई है जबकि एक किलो में दो रुपये रेट बढ़ गए हैं। नए रेट 16 तारीख से लागू होंगे।

बुलंदशहरः टहलने निकले हार्डवेयर व्यापारी के अपहरण से सनसनी

- खुर्जा से दिनदहाड़े कार में डालकर कारोबारी को ले गए बदमाश
- व्यापारियों में आक्रोश पुलिस कर रही जांच

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

बुलंदशहर। प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आज बुलंदशहर के खुर्जा में सुबह घर से टहलने निकले सत्तर वर्षीय हार्डवेयर व्यापारी राजकुमार का कार सवारों ने अपहरण कर लिया और फरार हो गए। दिनदहाड़े हुए इस घटना से पुलिस के होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

खुर्जा कोतवाली क्षेत्र की गोइनका कॉलोनी निवासी 70 वर्षीय राजकुमार की कबाड़ी बाजार चौराहे के निकट मथुरादास के नाम से हार्डवेयर की दुकान है। आज सुबह वह स्कूटी लेकर टहलने के लिए घर से निकले थे। जब वह नावल्टी मार्ग पर एनआरईसी कॉलेज के निकट पहुंचे तो कार सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाश व्यापारी को कार में डालकर फरार हो गए। व्यापारी की स्कूटी सड़क किनारे पड़ी देखकर स्थानीय लोगों ने उनके घर सूचना दी जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। व्यापारी के अपहरण की जानकारी पर स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है।

अफसरों के कामकाज से खुश नहीं है सांसद और विधायक!

» जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में जिला प्रशासन की करनी पर जनप्रतिनिधि तो अब अपना आपा तक खो दे रहे हैं। बाढ़ प्रभावित गोंडा तथा अंबेडकरनगर के साथ ही अलीगढ़ में तमाम कमी देखने के बाद जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ अपना मुंह खोला है। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अधिकारियों को उदासीन बताया है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता सूर्य प्रताप शाही बेहद सौम्य स्वाभाव के व्यक्ति हैं। सीएम योगी के आगमन से पहले शहर की व्यवस्था देखने के बाद वह काफी बिफर पड़े।

गोंडा में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों के बीच पहुंचे कैसरगंज से भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जब बाढ़ राहत कार्य में जिला प्रशासन की भूमिका के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि मत ही पूछिए तो अच्छा है। यहां तो बोलती ही बंद है, कुछ बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे और सुझाव देंगे तो माना ही नहीं जाएगा। इसी कारण चुप रहिए। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का प्रयागराज में दो दिन के प्रवास में बेहद ही खराब अनुभव रहा। अधिकारियों की निष्क्रियता से वह काफी हैरान दिखे और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। योगी सरकार में कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अलीगढ़ के जिला प्रशासन के साथ ही यहां के जनप्रतिनिधियों को लेकर विवादित बयान दिया है।

जनता के लखनऊ जाने का मतलब ईमानदारी से काम नहीं कर रहे अधिकारी

प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को कार्यप्रणाली सुधारने की हिदायत दी है। उन्होंने लोगों की जनसमस्याएं सुनीं। अधिकतर समस्या बिजली, पानी, चिकित्सा, सड़क से जुड़ी थी। उप मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को उसे 24 घंटे के अंदर निस्तारित करने का निर्देश दिया। कहा कि हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। समाज के अंतिम व्यक्ति को अधिकार, सम्मान व समस्त सुविधा दिलाना मोदी-योगी सरकार का लक्ष्य है। अधिकारी उसी मंशा के अनुरूप काम करें। कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या निस्तारित कराने के लिए लखनऊ का चक्कर काटता है तो इसका मतलब उस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को चिह्नित करके कार्रवाई की जाएगी।

हम तो रो भी नहीं पा रहे : बृजभूषण सिंह

गोंडा में बाढ़ से प्रभावित इलाकों का ट्रैक्टर से भ्रमण करने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह मीडिया कर्मियों से भी मिले। इस दौरान जब उनके बाढ़ राहत की व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो साफ कहा कि कुछ मत पूछिए तो ही अच्छा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन तो नकारा है। यहां पर तो सब भगवान भरोसे ही है। लोग तो अब वर्षा के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। यहां पर अब तो जब पानी रुकेगा तभी राहत मिलेगी। बृजभूषण शरण सिंह ने जब बाढ़ राहत कार्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जीवन में इससे खराब इंतजाम नहीं देखा। लोगों को हमारे समर्थकों ने ट्रैक्टर ट्राली पर बैठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हम भी तो ट्रैक्टर पर बैठकर ही क्षेत्र में घूम रहे हैं। घरों तक बाढ़ का पानी पहुंचा है। दो दशक बाद बाढ़ इतनी विकराल हुई और जिला प्रशासन मस्त है। सांसद से जब पूछा गया कि आपकी सलाह क्या है, तो उन्होंने कहा कि उनकी तो बोलती ही बंद है। अगर कुछ बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे।

ओडीओपी स्कीम में यूपी के 15 जिले फिसड्डी

» 11 ने लक्ष्य को पीछे छोड़ बनाया शानदार रिकॉर्ड

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। ओडीओपी स्कीम लागू करने में प्रदेश के 15 जिले फिसड्डी साबित हुए हैं, जबकि वर्तमान वित्त वर्ष के शुरुआती 6 माह में ही 11 जिलों का रिकॉर्ड शानदार रहा है। इन 11 जिलों ने लक्ष्य से कहीं ज्यादा काम करके दिखाया है। प्रदेश सरकार की इस योजना में नई इकाई स्थापित करने पर लिए ऋण पर 25 फीसदी तक सब्सिडी का प्रावधान है। योजना में जिलेवार नई इकाइयां स्थापित करने और उन्हें दी जाने वाली मार्जिन मनी (सब्सिडी) का लक्ष्य दिया गया है। शुरुआती छह माह में पूरे प्रदेश के लिए मार्जिन मनी स्वीकृति का 60 फीसदी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह लक्ष्य हासिल करने में कुल 47 जिले कामयाब रहे। वहीं, 15 जिलों ललितपुर, बिजनौर, देवरिया, चंदौली, बाराबंकी, बागपत, उन्नाव, कौशांबी, जालौन, झांसी, चित्रकूट, बदायूं, सोनभद्र, महोबा और बांदा की प्रगति रिपोर्ट 50 फीसदी से नीचे है। इनमें से बांदा, महोबा, सोनभद्र, बदायूं, चित्रकूट, झांसी, जालौन और कौशांबी में मार्जिन मनी स्वीकृति की प्रगति अभी तक 30 फीसदी भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर 11 जिले अमेठी, सीतापुर, गोंडा, संतकबीरनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, मेरठ, एटा, अलीगढ़ और हाथरस की प्रगति 101 से 182.10 प्रतिशत तक है। इटावा, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मथुरा, आजमगढ़, हरदोई, कानपुर देहात, रायबरेली, फतेहपुर, आगरा और फिरोजाबाद में भी प्रगति 81.72 से लेकर 99.79 प्रतिशत तक रही।

त्वरित भुगतान के साथ गन्ना किसानों से अधिकारी करें सीधा संवाद : लक्ष्मी नारायण

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। प्रदेश के गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने गुरुवार को राजधानी स्थित लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि वह गन्ना किसानों से सीधा संवाद स्थापित करें और उनकी समस्या का त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी तक 1,79,490 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है।

बकाया गन्ना भुगतान भी जल्द किया जाए। अधिकारियों ने बैठक में मंत्री को जानकारी दी कि पेराई सत्र 2020-21 में शत प्रतिशत किसानों को गन्ना भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2021-22 में भी लगभग 90 प्रतिशत किसानों को भुगतान किया जा चुका है। बाकी किसानों को गन्ना के बकाया धन का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। मंत्री ने बैठक में यह भी निर्देश दिए कि चीनी मिलें गन्ना किसानों को कृषि संयंत्र खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देकर उनकी मदद करें।

उन्होंने कहा कि पश्चिम उप्र में दीपावली के आसपास चीनी मिलें शुरू होंगी। इस बार मौसम के कारण गन्ना की फसल प्रभावित हुई है। ऐसे में इन सब पहलुओं को देखते हुए अभी से तैयारियां पूरी कर ली जाएं। चीनी मिलों के रिपेयर व मेंटीनेंस के कार्य व महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन भी समय पर कर लिया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास संजय भूसरेड्डी भी मौजूद रह गए।

दूसरे राज्यों में जाने वाली रोडवेज बसें की जाएं दुरुस्त : दुर्गा शंकर मिश्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों को प्रदेश से अन्य राज्यों में जाने वाली निगम की बसों की स्थिति बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी की बसों के सफर को आरामदायक बनाया जाए। इनकी सीटों को और अच्छा किया जाए।

दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों को नई तकनीक से लैस किया जाए। मुख्य सचिव ने परिवहन निगम की समीक्षा बैठक में कहा कि बसों में जीपीएस, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा और महिलाओं के लिए पिंक सीट लगवाई जाए। बसों में आपात स्थिति में लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग होनी चाहिए।

सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अनफिट, बिना परमिट, अवैध, ओवरलोड, जर्जर व डग्गामार बसों का संचालन न किया जाए। परिवहन विभाग ऐसी बसों के संचालन में विशेष सतर्कता बरतते हुए इन्हें हर हालत में रोके। मुख्य सचिव ने कहा कि तेज गति से वाहनों के संचालन व ओवरलोडिंग के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। यातायात नियमों का उल्लंघन पर वाहन का चालान किया जाए। परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि आठ राज्यों व नेपाल में जाने वाली कुल 2310 बसों का कायाकल्प किया जाएगा। लंबी दूरी की बसों की यात्रा सुगम व सुविधाजनक बनाने के लिए इसमें बसों की बाडी, सीटों आदि को ठीक करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

बामुलाहिजा

कार्टून : हसन जैदी

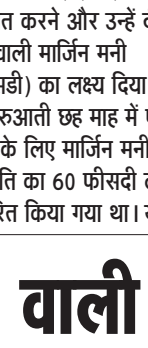

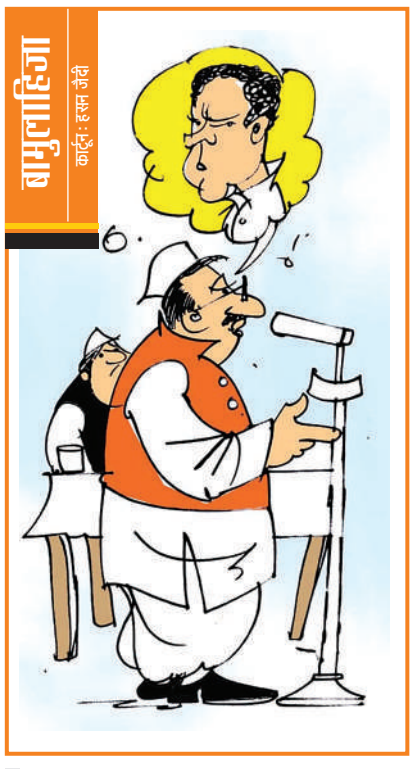

यूपी के एक हजार से ज्यादा प्रधानों का कार्यकाल डेढ़ साल में ही खत्म

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। प्रदेश में नई नगर पंचायतों के गठन, नगर पालिका परिषद और नगर निगमों के सीमा विस्तार से करीब एक हजार से अधिक ग्राम प्रधानों और दस हजार से अधिक वार्ड सदस्यों का कार्यकाल पांच की बजाय डेढ़ साल में ही खत्म हो गया है। ग्राम पंचायतों के निकायों में शामिल होने से ग्राम प्रधानों व वार्ड सदस्यों के राजनीतिक भविष्य पर तलवार लटक गई है। अप्रैल 2021 में हुए पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्य बनने के लिए उम्मीदवारों ने पूरे दम के साथ चुनाव लड़ा था।

चुनाव जीतने के बाद उन्होंने पांच वर्ष तक ग्राम प्रधान बनकर अपनी राजनीति संवारने का सपना देखा था। लेकिन सरकार ने इस दौरान 111 नई नगर पंचायतों का गठन और करीब 122 निकायों का सीमा विस्तार कर इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सरकार के इस फैसले से 45 जिलों की एक हजार से अधिक ग्राम पंचायतों का अस्तित्व खत्म

हो गया और ग्राम प्रधानों और वार्ड सदस्यों का कार्यकाल डेढ़ वर्ष में ही खत्म हो गया। पंचायतीराज विभाग के उप निदेशक योगेंद्र कटियार कहना है कि ग्राम प्रधान बनने की पहली शर्त है कि व्यक्ति उस ग्राम पंचायत का निवासी हो। ऐसे में नगर निकाय सीमा में शामिल होने के बाद ग्राम पंचायत का अस्तित्व ही समाप्त हो गया तो ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित व्यक्ति ग्राम प्रधान कैसे बना रह सकता है। जानकारों का मानना है कि भले ही ग्राम प्रधानों की कुर्सी चली गई है, लेकिन चेयरमैन के चुनाव में कोई भी दल उनकी अनदेखी नहीं कर सकता है।

यूपी में पूरे दमखम से निकाय चुनाव में उतरने की तैयारी में आप, संजय सिंह ने संभाला मोर्चा

» ट्रिपल सी फार्मूले से संगठन को मजबूत करने की रणनीति

» वार्ड प्रभारियों की नियुक्ति कमेटियां भी गठित

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। विधान सभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। खुद पार्टी के प्रदेश प्रभारी और आप सांसद संजय सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। वे अब सभाओं के जरिए लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में दमदारी से लड़ेगी। इसके लिए वार्ड और बूथ लेवल तक कमेटी तैयार कर ली गई हैं। आप भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम का मुद्दा लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगी। झाड़ू हमारा चुनाव चिन्ह है इसलिए हम से बेहतर सफाई कोई नहीं कर सकता।

आम आदमी पार्टी (आप) नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तेजी से संगठन विस्तार में जुटी है। पार्टी प्रकोष्ठों का विस्तार करने के साथ

ही शिक्षित लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। ट्रिपल सी में कैरेक्टर, करप्शन और क्रिमिनल शामिल हैं यानी साफ-सुथरी छवि, भ्रष्टाचार का आरोप न हो और कोई आपराधिक रिकार्ड न हो उसे ही पार्टी में इंट्री दी जा रही है। डॉक्टर, इंजीनियर व शिक्षक आदि पढ़े-लिखे लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। आप नगर निकाय चुनाव समिति के अध्यक्ष सभाजीत सिंह कहते हैं कि पार्टी संगठन में पदाधिकारी बनाने और चुनाव में प्रत्याशी बनाने से पहले स्क्रीनिंग कमेटी उस व्यक्ति के बारे में पूरी छानबीन करती है। आवेदन फार्म पर एक कालम इसका भी है कि कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं दर्ज है या भ्रष्टाचार आदि का आरोप तो नहीं है। आवेदन लेने के बाद पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी जिसमें संगठन के बड़े नेता, शिक्षाविद व अधिवक्ता शामिल हैं, वह जिला संगठन से संपर्क कर उसके बारे में पूरी छानबीन करते हैं। पार्टी के सभी प्रकोष्ठों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को आठ भागों में बांटकर संगठन विस्तार का काम तेज कर दिया है। सभी आठ भागों के अध्यक्ष, चार जोन के प्रभारी व तीन प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों के नामों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। यूपी प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बताया था कि अभी तक सात हजार वार्ड प्रभारी बनाए जा चुके हैं। तीन हजार वार्ड कमेटियों का गठन कर दिया गया है। उन्होंने बताया था कि 25 से 30 घर पर एक मोहल्ला प्रभारी बनाया जा रहा है।

विभिन्न मुद्दों पर भाजपा को घेरने की रणनीति

पानी, बिजली व सड़क इत्यादि की समस्याओं को जोर-शोर से उठाने के निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र व राज्य सरकार को पार्टी लगातार घेर रही है।

संगठन से जोड़ा जा रहा नए लोगों को: संजय सिंह

शुक्रवार को आगरा पहुंचे राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने कहा प्रदेश भर में कार्यकर्ता सम्मेलन करके हम कार्यकर्ताओं में दम भर रहे हैं और नए लोगों को जोड़कर संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। संजय सिंह स्वागत करने आए लोगों से बोले कि माला में पैसा खर्च न करें, पार्टी में चंदा दीजिए। वैसे ही नेताओं के दिमाग खराब हो जाते हैं। अनुशासन दिखाना जरूरी है, ये दिखाना भी होगा। दिल्ली-पंजाब में किया है, यूपी में भी करके दिखाएंगे।

गुजरात में मोर्चा संभालेंगे यूपी के मंत्री!

» योगी सरकार के तीन मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

» कई पदाधिकारी वहां कांग्रेस के गढ़ में खिलाएंगे कमल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। गुजरात विधान सभा चुनाव के रण में योगी सरकार के तीन वरिष्ठ मंत्रियों और प्रदेश से दो राज्य सभा सदस्यों को कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी सरकार के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर और परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह, राज्य सभा के मुख्य सचेतक लक्ष्मीकांत बाजपेयी और राज्य सभा सदस्य विजयपाल सिंह तोमर को गुजरात की जिन विधान सभा सीटों की कमान सौंपी गई है उनमें से अधिकांश पर कांग्रेस काबिज है। ऐसे में यूपी के इन धुरंधर नेताओं को वहां अपने अनुभव और राजनीतिक कौशल से पार्टी को बढ़त दिलानी होगी।

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को कच्छ जिले की अबडासा, मांडवी, भुज, अंजार, गांधीधाम (एससी) और रापर विधान सभा सीट का प्रभारी बनाया गया है। वर्तमान में गांधीधाम, भुज, अंजर, मांडवी सीट भाजपा के पास है जबकि अबडासा और रापर में कांग्रेस काबिज है। राज्य सभा के मुख्य सचेतक एवं राज्य सभा सदस्य लक्ष्मीकांत बाजपेयी को जूनागढ़ जिले का प्रभारी बनाया है। 2017 के विधान सभा चुनाव में जूनागढ़ की माणावदर, जूनागढ़, विसावदर, मांगरोल में कांग्रेस ने चुनाव जीता था जबकि भाजपा के हिस्से एक मात्र केशोद सीट आई थी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री लगातार चार चुनाव में चुनाव प्रबंधन के प्रभारी रहे सहकारिता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर को महिसागर जिले की बालासिनोर, लुणावाडा और संतरामपुर (एसटी) सीट का प्रभारी बनाया है। 2017 में संतरामपुर में भाजपा, बालासिनोर में कांग्रेस, लुनावाडा में निर्दल प्रत्याशी जीता था। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह को राजकोट जिले की राजकोट ग्राम्य (एससी), जसदण, गोंडल, जेतपुर, धोराजी विधान सभा का प्रभारी बनाया है। 2017 में धोराजी और जसदण में कांग्रेस ने चुनाव जीता था। वहीं राजकोट ग्रामीण, गोंडल और जेतपुर में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। राज्य सभा सदस्य विजयपाल सिंह तोमर को सोमनाथ जिले की सोमनाथ, तलाला, कोडीनार (एससी) व उना सीट की जिम्मेदारी मिली है। 2017 में ये सभी चार सीटें कांग्रेस की झोली में गई थी।

यूपी निकाय चुनाव में सियासी बिसात बिछाने में जुटी भाजपा

लोक सभा चुनाव से पहले भाजपा ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कमान संभाल ली है और रणनीति को अमलीजामा पहनाने की कोशिश में जुट गए हैं। भाजपा ने विपक्ष के लिए जमीन पर सियासी चक्रव्यूह तैयार करने के लिए एक ओर वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं वहीं वार्ड स्तर पर भी प्रभारियों के नियुक्ति का खाका तैयार कर लिया है। नगर निकाय चुनाव में सभी सीटों पर जीत का लक्ष्य तय कर भाजपा ने प्रदेश स्तर पर रणनीति तय कर ली है। क्षेत्रीय परिस्थितियों का आकलन करते हुए चुनावी मैदान सजाने के लिए आज से 17 अक्टूबर तक निकाय और वार्ड स्तर पर बैठकें होंगी। इसके बाद जल्द ही सभी वार्डों में प्रभारी भी नियुक्त कर दिए जाएंगे। भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में सभी सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए प्रदेश सरकार के मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निकायों का प्रभारी और सहप्रभारी बनाया गया है जबकि स्थानीय वरिष्ठ पदाधिकारियों को चुनाव संयोजन का जिम्मा सौंपा गया है। पिछले दिनों इन सभी के साथ प्रदेश मुख्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सहित उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक ने बैठक की। उन्हें चुनावी रणनीति समझाने के साथ ही आगामी कार्यक्रम और गतिविधियों की रूपरेखा समझाई गयी। प्रदेश नेतृत्व ने तय किया है कि निकाय स्तर पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठकें होंगी। इसके बाद वार्ड स्तर पर बैठकें प्रस्तावित की गई हैं।

एक हजार से अधिक कार्यकर्ता जाएंगे

गुजरात विधान सभा चुनाव में प्रचार के लिए यूपी से करीब एक हजार से अधिक भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता जाएंगे। अभी तक करीब दो सौ से अधिक कार्यकर्ता गुजरात पहुंच चुके हैं। आगामी दिनों में प्रदेश भाजपा टीम के साथ क्षेत्रीय टीमों, अग्रिम मोर्चों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी गुजरात जाएंगे।

नगर निकाय चुनाव में भी मंत्रियों की प्रतिष्ठ दांव पर

यूपी नगर निकाय चुनाव में योगी सरकार के मंत्रियों की साख दांव पर है। मंत्रियों पर न सिर्फ अपने गृह जिले के निकायों में पार्टी का परचम फहराने का जिम्मा है, बल्कि प्रभार वाले निकायों में भी जीत दिलाकर अपने राजनीतिक कौशल को साबित करना होगा। पार्टी ने सभी 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों सहित प्रमुख नगर पंचायतों में परचम फहराने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी नगर निगम की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी गई है। केशव न अनुभवी नेता हैं, बल्कि पिछड़े वर्ग में उनकी मजबूत पकड़ है। इसी तरह उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक को आगरा नगर निगम का जिम्मा सौंपा गया है। उनके साथ प्रदेश महामंत्री अश्विनी त्यागी को सह प्रभारी नियुक्त किया है। आगरा से मंत्री बेबीरानी मौर्य, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की भी प्रतिष्ठा जुड़ी है। पार्टी ने शाहजहांपुर में कौशल विकास राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिलदेव अग्रवाल को प्रभारी बनाया है।

जिद... सच की

Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जर्जर स्कूल, खतरे में नौनिहाल

अलीगढ़ में कस्बा बेसवां स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय के एक कमरे की छत गिरने से कक्षा में पढ़ रहे एक दर्जन से अधिक बच्चे मलबे में दब गए। इनमें तीन की हालत गंभीर है। इसके पहले बदायूं के प्राथमिक विद्यालय अंबियापुर की जर्जर बिल्डिंग के एक कमरे की छत गिर गई थी। गनीमत रही कि उस वक्त बच्चे अलग कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। वहीं जुलाई में गोंडा उच्च प्राथमिक विद्यालय के बरामदे की छत ढह गयी थी। ये घटनाएं यह बताने के लिए काफी हैं कि तमाम दावों के बावजूद प्रदेश के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प नहीं हो सका है और नौनिहाल जर्जर भवनों में जान-जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि जर्जर भवनों में बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? स्कूलों की मरम्मत के लिए हर साल जारी होने वाला करोड़ों का बजट कहां खर्च हो रहा है? सूची में दर्ज जर्जर स्कूलों के भवनों का ध्वस्तीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? किसके आदेश पर शिक्षकों और हजारों बच्चों की जान जोखिम में डाली जा रही है? क्या ऐसे ही जर्जर भवनों से शिक्षा को मजबूती दी जा सकेगी? क्या किसी को भी नौनिहालों के जीवन से खिलवाड़ करने की छूट दी जा सकती है?

यूपी में करीब 13 लाख सात हजार से अधिक प्राथमिक स्कूल हैं। इसमें डेढ़ करोड़ बच्चे पंजीकृत हैं। इन प्राथमिक विद्यालयों में एक से पांच तक की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। स्कूलों के कायाकल्प का दावा भी सरकार करती रहती है लेकिन हालत इसके ठीक उलट हैं। प्रदेश के हर जिले में दर्जनों स्कूल जर्जर भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। अकेले शाहजहांपुर में 400 प्राथमिक स्कूल जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं। वहीं फर्रुखाबाद में ऐसे स्कूलों की संख्या 139 है। यही हाल अन्य जिलों का है। शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विद्यालयों की संख्या अधिक है। हैरानी की बात यह है कि जर्जर भवन की सूची में दर्ज होने के बाद भी इनका ध्वस्तीकरण नहीं किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों को बगल में शिफ्ट कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर रहा है। हर साल मरम्मत के नाम पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं लेकिन जर्जर भवनों में सुधार नहीं हो रहा है। लिहाजा हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके कारण अभिभावक भी ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने से डर रहे हैं। यदि सरकार वाकई स्कूलों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा देना चाहती है तो उसे सबसे पहले इन जर्जर भवनों को सुधारना होगा। साथ ही ऐसे भवनों में कक्षा संचालित करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा मरम्मत और निर्माण के लिए अलग निगरानी तंत्र बनाना होगा।

सवाल यह है कि जर्जर भवनों में बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? स्कूलों की मरम्मत के लिए हर साल जारी होने वाला करोड़ों का बजट कहां खर्च हो रहा है? सूची में दर्ज जर्जर स्कूलों के भवनों का ध्वस्तीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? किसके आदेश पर शिक्षकों और हजारों बच्चों की जान जोखिम में डाली जा रही है? क्या ऐसे ही जर्जर भवनों से शिक्षा को मजबूती दी जा सकेगी?

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

नियंत्रण में है भारत का विदेशी कर्ज

अभिजीत मुखोपाध्याय

पिछले महीने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 2022 तक भारत पर विदेशी कर्ज 620.7 अरब डॉलर था, जो पिछले साल के आंकड़े (573.7 अरब डॉलर) से 8.2 प्रतिशत अधिक है। यह भी उल्लेखनीय है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विदेशी कर्ज का अनुपात, जो पिछले साल 21.2 प्रतिशत था, घट कर 19.9 प्रतिशत हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार के अनुपात में कुछ कमी आयी है। भारत के विदेशी कर्ज में 53.2 प्रतिशत अमेरिकी डॉलर में है जबकि भारतीय रुपये में लिये गये कर्ज का अनुपात 31.2 प्रतिशत है। दीर्घकालिक ऋण की मात्रा 499.1 अरब डॉलर आंकी गयी है, जो कुल कर्ज का 80.4 प्रतिशत है। इस राशि को लंबी अवधि में चुकाना है। जिन कर्जों को छोटी अवधि में चुकाना है, वह 121.7 अरब डॉलर है, जो विदेशी कर्ज का 19.6 प्रतिशत है।

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अुनसार बीते डेढ़ दशक में विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ता गया है। 2006 में यह कर्ज 139.1 अरब डॉलर था, जो अब 620 अरब डॉलर से अधिक हो गया है लेकिन इस अवधि में भारत की जीडीपी में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज का स्तर नियंत्रित रहा है। 2006 में यह अनुपात 17.1 प्रतिशत था, जो 2014 में बढ़ कर 23.9 प्रतिशत हो गया, लेकिन 2022 में यह 19.9 प्रतिशत तक आ गया जो 2019 के अनुपात के बराबर है। जब जीडीपी में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में बाहरी ऋण की मात्रा भी बढ़ती है क्योंकि आर्थिक गतिविधियों और निवेश में वृद्धि को लगभग हमेशा उधार से ही गति मिलती है। उस उधार का एक हिस्सा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार से लिया जा सकता है। जीडीपी की बढ़त के साथ विदेशी कर्ज के बढ़ने में कुछ भी असाधारण नहीं है। कर्ज चुकाने के लिए किसी भी देश के पास समुचित मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। 2008 में कुल कर्ज की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात 138 प्रतिशत हो गया था जो 2014 में गिरकर 68.2 प्रतिशत हो गया था लेकिन 2021 में यह 100.6 तथा 2022 में 97.8 प्रतिशत पहुंच गया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मौजूदा समय में ऋण चुकाने के उद्देश्य के लिए हमारे पास समुचित मात्रा में विदेशी मुद्रा उपलब्ध है। किसी देश का कर्ज अदा करने का अनुपात वह आंकड़ा है, जिसमें कर्ज (मूलधन और ब्याज दोनों) का भुगतान देश के निर्यात आय से किया जाता है। भारत का यह

अनुपात 2006 में 10.1 प्रतिशत था, जो 2011 में 4.4 और 2016 में 8.8 प्रतिशत रहा। इस साल इसके 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है इसलिए इस मोर्चे पर भी भारत के लिए तुरंत कोई चुनौती नहीं है।

कम अवधि के कर्ज की भारी मात्रा किसी अर्थव्यवस्था के विदेशी कर्ज चुकाने की क्षमता के लिए घातक हो सकती है. वर्ष 2006 में विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में भारत पर कम अवधि के कर्ज का अनुपात 12.9 प्रतिशत तथा कुल विदेशी कर्ज में ऐसे कर्ज का अनुपात 14 प्रतिशत था। 2013 में ये आंकड़े क्रमश: 33.1 और 23.6 प्रतिशत हो गये, पर 2021 में इनकी मात्रा क्रमश: 17.5 और 17.6 प्रतिशत पर आ गयी। 2022 में इनमें कुछ बढ़त हुई और ये 20 और 19.6 प्रतिशत के स्तर पर आ गये। इससे स्पष्ट है कि देश के समक्ष तुरंत कोई जोखिम नहीं है। गैर-वित्तीय निगमों पर सबसे अधिक बाहरी कर्ज (250.2 अरब डॉलर) है। हालांकि अभी चिंतित होने की कोई वजह नहीं है, पर वैश्विक अर्थव्यवस्था की मौजूदा हलचलों को देखते हुए भारत निश्चिंत भी नहीं रह सकता है। पहली बात यह है कि हाल के समय में डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में तेज गिरावट हो रही है। यही स्थिति बनी रही तो इससे बाहरी कर्जों तथा उनके भुगतान का बोझ बढ़ सकता है।

रुपये के दाम को थामने के लिए रिजर्व बैंक हस्तक्षेप करता रहता है, जिससे आरक्षित विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ सकती है। दूसरी भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति के दौर से गुजर रही है। यदि मुद्रास्फीति की गति ऐसी ही बनी रही, तो आगे भी रिजर्व बैंक को दरों को बढ़ाना पड़ सकता है। इससे आर्थिक वृद्धि धीमी हो सकती है। तब जीडीपी के तुलना में बाहरी कर्ज का अनुपात बढ़ सकता है। तीसरी बात यह है कि जब विदेशी कर्ज में गैर-सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है तो भविष्य में भुगतान से संबंधित जोखिम बढ़ने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। कर्ज चुकाने में परेशानी होने पर सरकार विदेशी देनदारों से बातचीत कर कुछ मोहलत या छूट हासिल कर सकती है, पर निजी क्षेत्र और बैंकों के लिए यह रास्ता उपलब्ध होना बहुत मुश्किल है। जोखिम के इस आयाम को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।

हिमस्खलन की त्रासदी से सबक लेना जरूरी

मुकुल व्यास

गत चार अक्टूबर को उत्तरकाशी जिले के द्रौपदी का डांडा-2 शिखर पर हिमस्खलन में 27 युवा प्रशिक्षु पर्वतारोहियों की मौत हो गयी। इसने पर्वतारोहण विशेषज्ञों को स्तब्ध कर दिया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में द्रौपदी का डांडा-2 शिखर पर पिछले तीन दशकों में हिमस्खलन का कोई इतिहास नहीं है। डांडा-2 चोटी समुद्र तल से 5,006 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पर्वतारोहण प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए यह चोटी सबसे सुरक्षित मानी जाती है। सुरक्षित स्थल होने के कारण सभी पर्वतारोहण संस्थान यहां प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। यह क्षेत्र देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों की नियमित निगरानी के अधीन भी है। वे यहां के हिमनदों की जांच करते रहते हैं। यहां के बारे में हमेशा अपडेट उपलब्ध रहते हैं।

हाल के दिनों में पर्वतीय राज्यों में हिमस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। हिमस्खलन की घटनाओं के बढ़ने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सितंबर के आखिरी कुछ हफ्तों में असामान्य रूप से भारी वर्षा के कारण उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। इसी वजह से हिमस्खलन की शुरुआत हुई होगी। सितंबर के आखिरी कुछ हफ्तों में उत्तरी भारत में भारी बारिश हुई। उत्तराखंड में कम ऊंचाई वाले इलाकों में तेज बारिश हुई जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फ गिरी। वाडिया इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ की चोटी पर जितनी बर्फ जमा हो सकती है, उससे अधिक बर्फ जमा हो गई है। यह अतिरिक्त बर्फ पहाड़ की ढलान से नीचे की ओर खिसकती है जिससे हिमस्खलन होता है। वाडिया इंस्टीट्यूट के एक सेवानिवृत्त हिमनद वैज्ञानिक डी.पी. डोभाल ने हिमस्खलन के लिए सितंबर में भारी बारिश को जिम्मेदार बताया। इस मानसून में राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक मात्रा में हिमपात हुआ है। जब एक चोटी की ढलान 40-50 डिग्री के कोण से अधिक हो जाती है और उस ढलान पर जमा बर्फ 2-2.5 फुट से अधिक होती है तब वजन और गुरुत्वाकर्षण के कारण हिमस्खलन होता है। केदारनाथ घाटी में 22 सितंबर, 26 सितंबर और 2 अक्टूबर को भी हिमस्खलन की घटनाएं हो चुकी हैं। उनमें से एक घटना केदारनाथ मंदिर से महज पांच किमी दूर चोराबाड़ी ग्लेशियर में हुई। यह पहला अवसर नहीं है जब उत्तराखंड में साल के इस समय हिमस्खलन हुआ है। नंदा देवी अभयारण्य के पास त्रिशूल चोटी पर पिछले साल एक अक्टूबर को चार नौसैनिक हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। दक्षिण-पश्चिम मानसून आमतौर पर सितंबर के पहले सप्ताह में उत्तराखंड से पीछे हटना शुरू कर देता है। इस बार सितंबर के आखिरी हफ्ते में भी बारिश हुई जो औसत से 20-59 प्रतिशत अधिक थी। सामान्य तौर पर हिमस्खलन की कई वजहें होती हैं। जब भौगोलिक स्थिति और वहां के वनक्षेत्र में कोई बदलाव होता है, तब भूस्खलन की आशंका बढ़ जाती है। दूसरी वजह हिमपात के दौरान बर्फ की मोटाई में होने वाला परिवर्तन। अगर इस दौरान इन इलाकों में हवा तेज चली तो हिमस्खलन हो सकता है।

भूकंप की वजह से भी हिमस्खलन होता है। हिमस्खलन बड़ी त्रासदी लाने में सक्षम होता है। सियाचिन से लेकर लाहौल तक ऐसे कई उदाहरण हैं, जब बड़ी संख्या में लोगों की मौत हिमस्खलन से हुई है। जिन क्षेत्रों में बड़े-बड़े पर्वतीय ढलान होते हैं, वहां भी हिमस्खलन की घटनाएं ज्यादा होती हैं। कई बार प्राकृतिक कारणों से बर्फ की बड़ी-बड़ी स्लैब इन्हीं ढलानों पर गिर जाती हैं। गिरते ही ये तेजी से नीचे की खिसकने लगती हैं। जब पर्वतीय क्षेत्रों में आंधी आती है तब भी भीषण तबाही मचती है। दरअसल, बर्फ के छोटे-छोटे कण और बर्फ के बड़े स्लैब, मिलकर आकार में बड़े हो जाते हैं। बर्फ के बड़े-बड़े कई स्लैब एक साथ खिसकने लगते हैं। जब वे अपने साथ मलबा और चट्टान लेकर खिसकते हैं, तब बड़ी त्रासदी होती है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हैंगिंग ग्लेशियर भी हिमस्खलन का कारण बनते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ पिघलने की दर तेज हो रही है। पहाड़ों के काटे जाने से हिमालय की नाजुक और ढीली पर्वतमाला गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। चाहे उत्तराखंड की पहाड़ियों में सड़कें, होटल हों या घरों का निर्माण, इस नुकसान की कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। इन पहाड़ियों पर मानव आबादी बढ़ रही है। सड़कों और अन्य विकास कार्यों के निर्माण के लिए पहाड़ों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। ये सभी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और प्रकृति के प्रकोप को आमंत्रित कर रहे है। कई पर्यावरणविद् चेता चुके हैं कि इन दुर्गम इलाकों में होने वाले निर्माण भविष्य में पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बदल देंगे। हिमस्खलन का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है लेकिन पहाड़ों पर जमा होने वाली बर्फ की नियमित निगरानी रख कर हादसों से बचा जा सकता है। वृक्ष रहित पहाड़ों पर हिमस्खलन का खतरा ज्यादा है। अत: पहाड़ों पर पेड़ों की अच्छी तादाद होनी चाहिए। पेड़ की टहनियों और शाखाओं के प्रतिरोध से हिमस्खलन की गति कम होती हैं। अन्य निवारक उपायों में पहाड़ों की ढलानों को सीढ़ीनुमा करना शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पहाड़ों पर जाने वाले पर्वतारोही और पर्यटक एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) से वाकिफ रहें तो हिमस्खलन के हादसों से बचा जा सकता है। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। इनके अलावा बचाव दलों का समय पर विपदा स्थल पर पहुंचना जरूरी है।

ये चीजें हड्डियों को धीरे धीरे बना देंगी खोखला

हड्डियों के प्रति लापरवाही और हमारी दिनचर्या में शामिल खराब खान-पान हड्डियों को नुकसान पहुंचाती हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हड्डियों का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। हड्डियों से जुड़ीं समस्याएं पहले बुजुर्ग लोगों के अंदर देखने को मिलती थीं, लेकिन खराब खान-पान के कारण कारण अब यह समस्या आम होती जा रही है और इस समस्या की चपेट में नौजवान भी आ रहे हैं। इस बारे में न्यूट्रीशनिस्ट अंजली मुखर्जी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखती हैं कि कैल्शियम काफी जरूरी खनिज है और आसानी से अवशोषित नहीं होता है। वहीं कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं जो कैल्शियम के अवशोषण को रोकते हैं जिससे हड्डियों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है।

कैफीन

कैफीन हमारे शरीर से कैल्शियम को बाहर निकालने का काम करती है जिससे हड्डियां धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं। चाय, कॉफी, कोका और चॉकलेट जैसे बेवरेज में पर्याप्त मात्रा में कैफीन मौजूद रहती है। इसलिए कैफीन का सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में करना चाहिए।

सॉफ्ट ड्रिंक

जब हम घर के बाहर होते हैं और तेज की प्यास लगी होती है तो हम तुरंत सॉफ्ट ड्रिंक लेकर पी लेते हैं लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक में शुगर और कैफीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है। वहीं, प्रिजर्वेटिव(परिरक्षक) के रूप में फॉस्फेरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जो हड्डियों में कैल्शियम को खत्म करने का काम करता है।

शुगर और नमक की अधिकता

शुगर और नमक का अधिक सेवन हड्डी की सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसके अधिक सेवन से कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ जाता है। ब्रेड और चिप्स में सबसे ज्यादा नमक पाया जाता है, जो हड्डियों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है।

धूम्रपान और तंबाकू

धूम्रपान और तंबाकू का सेवन हड्डियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तंबाकू में मौजूद निकोटिन, शरीर के कैल्शियम के अवशोषण की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे हड्डियां धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं।

एनिमल प्रोटीन

हमारा शरीर दो तरह से प्रोटीन को ग्रहण करता है। पहला जो साग-सब्जियों से मिलता है, जैसे- दाल, फल, सब्जी आदि। दूसरा जो हमें जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे- अंडा, चिकन, मटन आदि। न्यूट्रीशनिस्ट अंजली मुखर्जी कहती हैं कि जानवरों (एनिमल) से प्राप्त होने वाले प्रोटीन के ज्यादा उपयोग से बचना चाहिए। एनिमल प्रोटीन के ज्यादा सेवन से कैल्शियम की कमी हो सकती है।

कम मांसपेशी

ऐसा माना जाता है कि कम मांसपेशियों वाला व्यक्ति भी कम कैल्शियम जमा कर पाता है, जो हड्डियों के लिए नुकसानदायक है। कैल्शियम का अवशोषण सही तरह से हो, इसके लिए भोजन में कैल्शियम के साथ-साथ मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, सी और विटामिन डी के साथ लेना चाहिए। साथ ही सप्ताह में 6 दिनों के लिए कम से कम 30 मिनट के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए।

ज्यादा देर तक बैठे रहने की आदत

न्यूट्रीशनिस्ट अंजली मुखर्जी के अनुसार, ज्यादा बैठे रहने की लाइफस्टाइल भी हमारी हड्डियों को नुकसान पहुंचाती है। दरअसल, जब हम एक ही स्थान पर लंबे समय तक बैठे रहते हैं उससे हमारे शरीर का मूवमेंट नहीं होता है, जिससे हड्डियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में हड्डियों को नुकसान से बचाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी जैसे चलना, टहलना या दौड़ना चाहिए।

हंसना मना है

रोहन और मोहन बात कर रहे थे... रोहन - मेरा बॉस सबको परेशान करता था। तो कल शाम को मैंने उसके खाली टिफिन में चुपके से एक चॉकलेट रख दी और एक पर्ची डाल दी। पर्ची में लिखा था-जानू दोनों तुम ही खाना, उस पागल को मत देना। आज बॉस लंगड़ाते हुए ऑफिस आया था, चेहरा इतना सूजा हुआ था कि एक आंख भी नहीं खोल पा रहा था।

करवा चौथ के दिन पति- तुम बदली-बदली सी लग रही हो पत्नी- हां सिर्फ आज के लिए

सोनू अपने दोस्त मोनू को ज्ञान बांट रहा था,अगर परीक्षा में पेपर बहुत कठिन हो तो, आंखें बंद करो....गहरी सांस लो और जोर से कहो- ये सब्जेक्ट बहुत मजेदार है इसलिए अगले साल इसे फिर पढ़ेंगे...

पप्पू - बेकार ही कहते हैं लोग कि पत्नियां अपनी गलती नहीं मानती हैं, मेरी वाली तो रोज मानती है...! गप्पू - अच्छा, क्या बोलती है...? पप्पू - कहती है, गलती हो गई तुमसे शादी करके...!

सोनू- सर मेरी बीवी 4-5 दिनों के लिए मेरे साथ कहीं घूमने जाना चाहती है, छुट्टी चाहिए. बॉस - नहीं मिलेगी. सोनू - थैंक्यू सर, मैं जानता था मुसीबत में आप ही मेरे काम आएंगे..

भंडारे में धक्का मुक्की से मोटा आदमी एक खूबसूरत लड़की से टकरा गया... इस टक्कर में मोटे आदमी के एक टांग की हड्डी टूट गई.. वो हॉस्पिटल गया तो देखा कि वहां एक आदमी की दोनों टांगें टूटी हुई हैं। भोलापन तो देखिए... वो उसको देखकर बोला- आपकी दो पत्नियां हैं क्या??

कहानी | राजा और चांद

अकबर ने एक बार बीरबल को किसी काम के लिए काबुल भेजा। वहां पर उन्हें एक जासूस समझ कर वहां के राजा के सामने पकड़ कर लाया गया। राजा : तुम कौन हो और मेरे राज्य में क्या कर रहे हो ? बीरबल : मैं भारत से आया हुआ एक मुसाफिर हूं। राजा : अगर तुम इतने बड़े यात्री हो तो बताओ तुम मेरे शासन के बारे में क्या सोचते हो ? बीरबल : आप पूर्ण चन्द्रमा की तरह हैं, आपकी ताकत और साहस की कोई तुलना नहीं है। राजा इस उत्तर से संतुष्ट हुए, लेकिन पूछा - तुम्हारे राजा के बारे में ? बीरबल : वे एक नये चांद की तरह हैं जिनकी तारीफ करने को ज्यादा कुछ नहीं है। राजा इतना खुश हुआ कि उसने बीरबल को एक थैला भरकर सोने की मोहरें दीं। उसके लौटने पर, अकबर के दरबारियों ने पहले ही बादशाह को बीरबल और काबुल के राजा के बीच हुई बातें बता दीं। अकबर : बीरबल, मैंने सुना तुम्हें काबुल के राजा ने सम्मान दिया। बीरबल : हां, जहांपनाह। उन्होंने मुझसे आपके बारे में पूछा। अकबर : मैंने सुना कि तुमने उन्हें पूरे चंद्रमा और हमारी नये चांद तुलना की। बीरबल : यह सच है, जहांपनाह। अकबर : तुम्हारी अपने बादशाह की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई ? बीरबल : मैंने तो आपकी प्रशंसा की। बढ़ता हुआ चंद्रमा तो बढ़ती समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और उससे प्रशंसा भी बढ़ती है हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही चन्द्रमा को दूसरे दिन से देखना शुरू करते हैं। जबकि पूर्ण चन्द्रमा की शक्ति और ऊर्जा धीरे-धीरे कम होती जाती है। अकबर : मैं तुम पर पूर्ण विश्वास कर सकता हूं।

शिक्षा : अपने संदेश को इस प्रकार संप्रेषित करें कि प्राप्तकर्ता वही देखे जैसा वह चाहता है और उससे किसी की हानि भी न हो। कूटनीति एक कला है- इसे सीखें और पारंगत हों यदि आप शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। यह वाहन में ईंधन की तरह ही आवश्यक है।

5 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष कुछ तनाव और मतभेद आपको चिड़चिड़ा और बेचैन बना सकते हैं। आप ऐसे स्रोत से धन अर्जित कर सकते हैं, जिसके बारे में आपने पहले सोचा तक न हो।

वृषभ आज का दिन कार्यक्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला रहेगा। माता-पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। कोर्ट-कचहरी के किसी मामले में फैसला आपके पक्ष में रहेगा।

मिथुन धन लाभ की संभावनाएं हैं। आपके पास बहुत काम बकाया है जैसी भी स्थिति हो आप यह सब काम प्रभावी तरीके से पूरा कर लेंगे। दोस्तों से दूरी बनाए रखे।

कर्क स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है। आपकी खुशमिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। जमा-पूंजी पारम्परिक तौर पर निवेश करें।

सिंह आज परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। इस राशि के बुक सैलर के लिए आज का दिन लाभ दिलाने वाला हो सकता है।

कन्या गृहस्थी में समस्या हो सकती है. नौकरीपेशा जातकों के लिए भी रैंक और पारिश्रमिक के संबंध में सुधार संभव है। खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।

तुला आज आप खुद को सुकून में और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे। आपके मन में जल्दी पैसे कमाने की तीव्र इच्छा पैसा होगी।

वृश्चिक आज ऑफिस में बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पूरे दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। इस राशि के राजनीति से जुड़े लोगों के लिये आज विदेश दौरे के चांस बन रहे हैं।

धनु आज व्यापार के क्षेत्र में आप अलग पहचान बनाने में कामयाब होंगे। आपका जीवनसाथी और बच्चे खुशी का स्रोत होंगे। अपने दोस्तों से दूर रहे।

मकर आज अपनी सेहत के चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। आपके आस-पास के लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे व सराहेंगे। घूम फिरने जा सकते हैं।

कुम्भ रूके हुए सारे काम आसानी से पूरे हो जायेंगे। अगर आप अपने बड़े भाई-बहनों के सहयोग से किसी भी काम को शुरू करेंगे, तो उसमें आपको तरक्की जरूर मिलेगी।

मीन आज आप जीवन के प्रति आपके नजरिये में सकारात्मक बदलाव लाएंग। परिवार के सदस्यों के साथ छोटी यात्राओं या भ्रमण की योजना बन सकती है।

डबल एक्सएल के लिए हुमा सोनाक्षी ने कम किया वेट

हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा की पहली मुद्दे वाली कॉमेडी फिल्म डबल XL जल्द रिलीज होने वाली है। इसे हेलमेट फेम सतराम रमानी ने डायरेक्ट किया है। वहां उन्होंने कंडोम के मुद्दे के ईद गिर्द कहानी बुनी थी। अब इस फिल्म के जरिए उन्होंने वजनी महिलाओं की बॉडी शेमिंग के मसले पर सटीरिकल टेक लिया है। बातचीत के दौरान हुमा और सोनाक्षी ने बताया कि डायरेक्टर को इस फिल्म का आइडिया ही उनके वजन के चलते आया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो रियल लाइफ में बॉडी शेमिंग झेल चुकी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसकी वजह से एक समय उनका आत्मविश्वास भी हिल गया था। सोनाक्षी को कुछ समय पहले एक वजनी प्रोड्युसर ने वजन तक कम करने को कहा था इस बारे में बात करते हुए वो कहती हैं, मैं वो फिल्म साइन कर चुकी थी। फिल्म के फ्लोर पर जाने से ठीक दस दिन पहले मुझसे उस प्रोड्यूसर ने कहा कि अगर आप वेट लूज नहीं करोगे, तो हम आप को रिप्लेस कर देंगे। वो भी तब, जबकि वो प्रोड्युसर मेरे पुराने जानने वाले थे। इसके साथ ही वो खुद बहुत ओवरवेट थे। मैं उनके उस रवैये और गट्स को देखकर सरप्राइज?ड हो गई थी कि उन्होंने ऐसा कह कैसे दिया। इन सबके बाद मैंने वो फिल्म की।

बॉलीवुड | मसाला

मिर्जापुर के तीसरे सीजन पर रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वेब सीरीज मिर्जापुर के तीसरे सीजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह बेहतर याचिका दायर करें। कोर्ट इस पर भी अश्चर्य जताया कि आखिर किसी वेब सीरीज के लिए 'प्री-स्क्रीनिंग' समिति कैसे हो सकती है। न्यायालय ने कहा कि यह हमेशा महसूस किया गया है कि 'प्री-सेंसरशिप' अनुमति योग्य नहीं है। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह आश्चर्य भी जताया कि सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब श्रृंखलाएं, सिनेमा या अन्य कार्यक्रमों के लिए कोई 'प्री-स्क्रीनिंग' समिति कैसे हो सकती है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ मिर्जापुर निवासी सुजीत कुमार सिंह की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब श्रृंखला, सिनेमा या अन्य कार्यक्रमों के लिए 'प्री-स्क्रीनिंग' समिति बनाये जाने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने कहा, ''वेब श्रृंखला के लिए कोई प्री-स्क्रीनिंग समिति कैसे हो सकती है? एक विशेष कानून है। जब तक आप यह नहीं कहते कि ओटीटी (ओवर-द-टॉप) भी इसका (कानून का) एक हिस्सा है। आपको कहना होगा कि मौजूदा कानून ओटीटी पर भी लागू हो। (इसके बाद) कई सवाल उठेंगे, क्योंकि प्रसारण दूसरे देशों से होता है। पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने का निर्देश देते हुए कहा, ओटीटी उपग्रह प्रसारण अन्य देशों से होता है, भले ही दर्शक यहां हों। प्रदर्शन के बाद निवारण तंत्र अलग है। बेहतर (याचिका) दायर करें। शीर्ष अदालत ने मिर्जापुर के तीसरे सीजन पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया।

बॉलीवुड | मन की बात

विक्की कौशल के साथ समय नहीं बिता पा रहीं कटरीना

कटरीना कैफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शादी के बाद अपनी जिंदगी बदलने और अपने पति विक्की कौशल को लेकर खुलकर बात की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शूटिंग की वजह से उन्हें विक्की के साथ ज्यादा समय बिताने को नहीं मिल पाता है। कटरीना से बातचीत के दौरान पूछा गया कि शादी के बाद उनकी लाइफ में क्या बदलाव आए हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा, शादी सबकी लाइफ में बड़ा बदलाव लाती है। आप किसी के साथ अपनी जिंदगी बांट रहे होते हैं और उनके साथ जिंदगी भर रहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सफर है। हम ज्यादातर शूट के लिए बाहर ही रहते हैं, मुझे लगता है हर एक्टर की लाइफ में ऐसा होता है। कटरीना आगे कहती हैं, हमें बहुत ट्रैवल करना होता था, जिसकी वजह से हमें एक-दूसरे के साथ बहुत ही कम समय बिताने को मिल पाता है। लेकिन वो काफी शानदार इंसान हैं और उनके जैसे इंसाना का मेरी लाइफ में होना सबसे अच्छी बात है। कटरीना और विक्की पिछले साल 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सिक्स सेंसेस फोर्ट में शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों 2019 से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। वर्कफंट की बात करें तो कटरीना जल्द ही हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन भूत में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में उनके साथ सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर भी हैं। इसके अलावा वो सलमान खान के साथ फिल्म टाइगर 3 में भी दिखाई देंगी।

जापान के इस टॉयलेट की हर जगह हो रही है चर्चा, आखिर क्या है इसमें खास

मेहनत, डेडिकेशन तकनीक और इनोवेशन में जापान का कोई जवाब नही है। यहां के लोग और इंजीनियर्स हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तभी तो ये देश सालों से तरक्की के रास्तों पर चल रहा है। अब पर्यावरण संरक्षण को ही लीजिए। पिछले कुछ वर्षों में, लोग इसको लेकर काफी जागरूक हो गए हैं। लोग लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं लेकिन जापान की बात ही कुछ और है। वो इस मसले को लेकर बेहद गंभीर है। अब जरा वहां के इस टॉयलेट के डिजाइन को ही देख लीजिए। पानी बचाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। लोग इन दिनों के जापान के टॉयलेट में लगे इस कमोड की चर्चा कर रहे हैं। जरा इसे ध्यान से देखिए शौचालय में एक फ्लश टैंक है जिसके ऊपर एक हैंडवाशिंग सिंक है। हाथ धोने से निकलने वाला साबुन का पानी फ्लश टैंक को भरने में योगदान देता है। इस प्रक्रिया में पानी की बचत होगी। कहने की जरूरत नहीं है कि सिंक पर लगे नल का पानी ताजा होता है लेकिन इस तरीके से पानी की काफी ज्यादा बचत होगी.इतना ही नहीं इस डिजाइन से बाथरूम में जगह की भी बचत होती है। कॉम्पैक्ट वॉशरूम का उल्लेख करते हुए एक ट्वीट में दावा किया गया कि जापान इन शौचालयों के व्यापक उपयोग के माध्यम से लाखों लीटर पानी बचाता है। ये ट्वीट 1 लाख से ज्यादा लाइक्स के साथ वायरल हो गया है। इसने कुछ दिलचस्प सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को भी सामने लाया है जो यूजर्स को खासा पसंद आ रहा है। हालांकि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं भी आ रहा है। लोग इसे बेकार करार दे रहे हैं। कुछ यूजर्स ने ये भी बताया है कि इस तरह सिंक में हाथ धोना काफी असुविधाजनक होगा। एक व्यक्ति ने यह कहते हुए ट्वीट किया कि डिजाइन यदि आपके पास लंबी बाहें हैं तो इसका उपयोग करना वास्तव में सुविधाजनक लगता है।

अजब-गजब | यहां 15 दिनों के लिए खुला नरक का दरवाजा!

भूखे भूत-प्रेतों को खाना खिला रहे लोग

दुनिया में कई ऐसी जगहे हैं जो भूत-प्रेत की वजह से हमेशा चर्चा में रहती है। कई लोग इन पर यकीन नहीं करते हैं, तो कुछ इन्हें लोग मानते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश है जहां भूत-प्रेतों को खाना खिलाया जाता है और यह सिलसिला 15 दिनों तक चलता है। इसके पीछे एक खास वजह बताई जाती है जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे।

बताया जाता है कि यहां पर अगर भूतों का खाना नहीं खिलाया जाता है, तो बुरी आत्माएं और भूत परिवार के लोगों को परेशान करते हैं। अब यह कितना सच है और कितना झूठ इस बारे में हम नहीं बता सकते हैं। हालांकि लोगों की इसके पीछे एक मान्यता है जिसकी वजह से वह ऐसा करते हैं। आपने भी भूत-प्रेत की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ऐसी मान्यता के बारे में शायद ही पहले कभी सुना हो। आइए जानते हैं कि आखिर यह मान्यता और इसकी वजह क्या है?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एशियाई देश कंबोडिया में इस तरह की मान्यता है। इस देश में शरद ऋतु के दौरान एक त्योहार मनाया जाता है जिसे पचम बेन फेस्टिवल (Pchum Ben festival) के नाम से जाता है। हर साल सितंबर और अक्टूबर के बीच खमेर चंद्र कैलेंडर के 10 महीने में 15 दिनों तक यह त्योहार चलता है।

कंबोडिया में मान्यता है कि इस त्योहार के दौरान नरक के दरवाजे 15 दिनों के लिए खुल जाते हैं। इसके बाद बुरी आत्माएं और भूत बाहर आ जाते हैं और यह भूखी होती हैं। इनको शांत करने के लिए खाना खिलाया जाता है। इस त्योहार में चार प्रकार के भूत और आत्माएं होती हैं। एक अस्थायी रूप से मुक्त आत्माएं होती हैं जो खून पीती हैं। इसे खमेर महोत्सव के तौर पर जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान मंदिरों, कब्रिस्तानों और अपने रिश्तेदारों के घरों के आसपास भूत घूमते हैं और अच्छे खाने की तलाश करते हैं। अगर इन भूतों को अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो लोगों को परेशान करते हैं। कंबोडिया में लोग इस मान्याता को बहुत अधिक मानते हैं। यहां पर लोग अपने सात पूर्वजों को खाना खिलाते हैं।

बताया जाता है कि त्योहार शुरू होने के पहले दिन लोग सूरज निकलने से पहले ही भोजन बना लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, क्योंकि भूत रोशनी नहीं पसंद करते हैं। अगर थोड़ी सी भी सूरज की रोशनी दिख गई, तो भूत भोजन स्वीकार नहीं करते हैं और लोगों को पापों की सजा मिलती है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंबोडिया एक भिक्षु ने कहा कि मान्यता है कि कुछ लोगों को उनके पाप की सजा मिलती है जिसकी वजह से वह नरक में चले जाते हैं। नरक में उनको काफी प्रताड़ित किया जाता है और पीड़ा होती है। नरक में लोगों को न कपड़े मिलते हैं और न ही खाना। फचम बेन के दौरान परिजन आत्माओं को भोजना कराते हैं, ताकि उनकी पीड़ा कुछ कम हो सके।

हिमाचल विधान सभा चुनाव की तारीख तय, रिवाज बदलने की तैयारी में भाजपा

» दोबारा सरकार बनाने के लिए बहाना होगा भाजपा को पसीना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

शिमला। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल में चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी है। हिमाचल में 12 नवंबर को एक फेज में चुनाव होगा और 8 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। इस बीच भाजपा को हिमाचल में रिवाज बदलने यानी प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने के लिए खूब पसीना बहाना होगा।

प्रदेश में 1985 के बाद हर पांच साल बाद नई सरकार चुनने की परंपरा रही है। छह बार प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सरकार रिपीट करने के लिए हर चुनाव में एड़ी-चोटी का जोर लगाया था मगर प्रदेश की जनता के आगे उनकी एक न चली। भाजपा ने पांच-पांच साल की परंपरा को समाप्त करने के लिए इस बार रिवाज बदलने का नारा दिया है। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की जनता ने पांच-पांच साल की परंपरा को बदला है। दोनों राज्यों में रिवाज बदलने से हिमाचल भाजपा को भी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। विधान सभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी व पुरानी पेंशन योजना (ओपीसी) की बहाली मुख्य होंगे। भले ही यहां कांग्रेस कई गुटों में बंटी है लेकिन वह 10 माह पहले हुए तीन विधान सभा व मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव की तरह टक्कर दे सकती है। उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को चारों सीटों पर शिकस्त दी थी। उपचुनाव में कांग्रेस ने महंगाई व बेरोजगारी को जनता के बीच भुनाया था। इस बार भी कांग्रेस उसी तैयारी में है। भाजपा की तरफ से शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल दो-दो बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। शांता कुमार दोनों बार कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए थे। 2002 व 2012 के चुनाव में प्रेम कुमार धूमल ने मिशन रिपीट का नारा दिया था, जिसे जनता ने नकार दिया।

प्रदेश में 12 नवंबर को होगा मतदान
8 दिसंबर को आएगा परिणाम

हिमाचल प्रदेश में विधान सभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को नई दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल में एक चरण में पूरे प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। हिमाचल में विधान सभा चुनाव की अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी होगी। चुनाव लड़ने के लिए 25 अक्टूबर से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। इनकी छंटनी 27 को होगी जबकि 29 अक्टूबर को नाम वापस ले सकेंगे। प्रदेश में आचार संहिता लागू होते ही सरकारी घोषणाओं और नई भर्तियों पर भी रोक लग गई है।

नया वाहन खरीदते समय देना होगा नामिनी का भी नाम

» परिवहन विभाग का अहम निर्णय, स्वामित्व-हस्तांतरण के मामलों में भी होगी सुविधा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यदि आप वाहन खरीद रहे हैं तो आपको अपने नामिनी का नाम भी देना होगा और पंजीयन प्रमाण पत्र में नाम उसका नाम भी दर्ज होगा। वाहन मालिक की मृत्यु के बाद वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण को लेकर खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते परिवहन विभाग ने यह कदम उठाया है। वाहन मालिक के बाद वहीं व्यक्ति वाहन का स्वामी होगा जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र में नामिनी की जगह नाम होगा।

अपर परिवहन आयुक्त राजस्व लक्ष्मीकांत मिश्रा ने प्रदेश के सभी परिक्षेत्रों के उप परिवहन आयुक्तों के साथ ही संभागीय परिवहन अधिकारियों व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को इसकी व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि वाहन मालिक की मृत्यु की दशा में वाहन के स्वामित्व-हस्तांतरण के मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अपर परिवहन आयुक्त राजस्व ने बताया कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्वामित्व-हस्तांतरण के मामलों में आ रही समस्याओं को देखते हुए ये निर्देश दिए हैं। राजधानी में आरटीओ कार्यालय में 20 हजार से अधिक वाहनों के तबादले अटके हुए हैं। इनमें वाहन मालिक की मृत्यु हो जाने के बाद कई लोग उसके लिए दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। विभागीय कर्मचारियों से त्रुटिवश किसी के नाम वाहन दर्ज करा दिया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जाती है।

सरदारशहर सीट पर उपचुनाव गहलोत के लिए होगा लिटमस टेस्ट

» राजस्थान में सियासी संकट के बीच सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान में चूरू जिले की सरदारशहर विधान सभा सीट से कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन से एक बार फिर से विधान सभा उपचुनाव होना तय हो गया है। विधान सभा चुनाव 2023 से पहले कांग्रेस और भाजपा के लिए इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है।

राजस्थान में सियासी संकट के बाद सीएम अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इससे पहले उपचुनाव में कांग्रेस ने उदयपुर की वल्लभनगर व प्रतापगढ़ के धरियावद विधान सभा सीट पर शानदार जीत दर्ज की थी। गहलोत और पायलट कैंप की खींचतान के बीच कांग्रेस के लिए यह उपचुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। सीएम गहलोत योजनाओं के सहारे वोटर्स को लुभाएंगे, वहीं भाजपा कानून व्यवस्था पर घेरने की कोशिश करेगी। विधान सभा चुनाव 2018 में कांग्रेस को राज्य में 99 सीटें मिली थी लेकिन चुनावों के बीच अलवर की रामगढ़ सीट पर बसपा प्रत्याशी का निधन हो गया था, जिससे चुनाव आयोग ने रामगढ़ सीट का चुनाव स्थगित कर दिया था। बाद में जब यहां चुनाव हुए तो कांग्रेस की ओर से साफिया जुबैर चुनाव जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस ने झुंझुनूं की मंडावा सीट जीतकर दमदार तरीके से एंट्री की। हालांकि, कांग्रेस को खींवसर विधान सभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। चूरू की सुजानगढ़ और भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा उपचुनाव भी कांग्रेस जीतने में सफल रही। हालांकि, राजसमंद से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब तक हुए विधान सभा उपचुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली है। कांग्रेस विधान सभा उपचुनाव हार जाती है तो इसे सीएम गहलोत के लिए बड़ा झटका माना जाएगा।

सत्येंद्र जैन को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करने की मांग खारिज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करने वाली याचिका को जुर्माना लगाकर खारिज कर दिया है।

याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 16 अगस्त को इस संबंध में याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह जैन को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित नहीं कर सकता और उन्हें विधान सभा की सदस्यता व दिल्ली सरकार के मंत्री के तौर पर अयोग्य नहीं ठहरा सकता। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने कहा, याचिका बेहद भ्रामक और न्यायिक समय की बर्बादी है इसलिए याचिकाकर्ता पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाने की जरूरत है। पीठ ने निर्देश दिया कि यह रकम सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के पास जमा की जाए।

मोदी पर ललन सिंह का बड़ा हमला, कहा, बहुरूपिया हैं पीएम

» जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया डुप्लीकेट ओबीसी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डुप्लीकेट ओबीसी बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम बहरूपिया हैं। वे घूम-घूमकर खुद को पिछड़ा वर्ग का बताते हैं जबकि वे असल में ओबीसी नहीं बल्कि डुप्लीकेट हैं। ललन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने कहीं पर भी चाय नहीं बेची बल्कि ढोंग कर रहे हैं।

पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में शुक्रवार को मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न दलों के कई नेताओं ने जेडीयू की सदस्यता ली। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने पीएम मोदी पर जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरूपिया हैं। बहरूपिया जैसे 12 दिन में 12 रूप दिखाता है, मोदी भी ठीक वैसे ही हैं। मगर पिछड़े समाज के लोगों के बीच आकर इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। ललन सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने अपनी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया था इसलिए वे डुप्लीकेट ओबीसी हैं, असली नहीं हैं।

भाजपा ने साधा निशाना

जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणी पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। बिहार भाजपा के नेता जनकराम ने कहा कि ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र का तकाजा है। इस कारण वे निराशा और हताशा में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं।

गुजरात में आम आदमी पार्टी भी रेस में

» 4पीएम की परिचर्चा में उठे कई सवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। देश की राजनीति में इस समय यह सवाल चर्चा में है कि क्या अरविंद केजरीवाल गुजरात में पीएम मोदी का खेल बिगाड़ देंगे? उनका गणित किसका नुकसान करेगा कांग्रेस का या भाजपा का? इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार अनिल जयहिंद, धनंजय कुमार, दिनेश के वोहरा, वंशराज (आप प्रवक्ता) और 4पीएम के संपादक संजय शर्मा ने एक लंबी परिचर्चा की।

धनंजय कुमार ने कहा कि इस बार का गुजरात विधान सभा चुनाव गुजरात का नहीं है। उसका स्तर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। मोदी और एंटी मोदी वोटर्स में इस बार भाव अलग है। 2017 में जब मोदी का जादू चल रहा था तब कांग्रेस ने उनके पसीने छुड़ा दिए थे। 99 पर रोक दिया था।

परिचर्चा

रोज शाम को छह बजे देखिए 4PM News Network पर एक ज्वलंत विषय पर चर्चा

डॉ. अनिल जयहिंद ने कहा कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी का भारतीय ट्राइबिल्स पार्टी का गठबंधन होते-होते रह गया जबकि 27 सीटों पर गुजरात में असर है। मोदी का जो गुजरात मॉडल है, वो शहरी के लिए ज्यादा है। गरीब तबका नाराज है। दिनेश के वोहरा ने कहा कि किसी को भनक नहीं लग रही कि हो क्या रहा। गुजरात में लड़ाई इस बार तगड़ी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से फाइट है। आम आदमी पार्टी की स्टाइल अलग है। वे शो नहीं करते कि किसके साथ हैं।

वंशराज ने कहा कि जब से अरविंद केजरीवाल की पार्टी गुजरात में सक्रिय हुई, वहां की परिस्थितियां बदल गई है। मोदी के पहले और अब के भाषण में अंतर तो है। कई सीटें खिसक रही हैं, इससे मोदी डरे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल स्कूल, अस्पताल, बिजली और नौकरी की बात करते हैं। गुंडा व मवालियों जैसी बात नहीं करते।

समृद्ध प्रदेश है यूपी, यहां हैं अपार संभावनाएं : सीएम

» मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डाक टिकट प्रदर्शनी का किया शुभारंभ

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। अलीगंज स्थित ललित कला अकादमी में आयोजित तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफिलेक्स का आज शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम वन गमन पथ के विशेष आवरण और विरूपण का विमोचन किया।

उन्होंने कहा कि भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास रहा है। उन्होंने 12 वर्ष उत्तर प्रदेश में व्यतीत किये हैं। चित्रकूट इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उस समय साधन नहीं थे। एक एक सतंभ इसका गवाह है वह किन मार्गों से होकर गुजरे थे। अभी 17 अक्टूबर को भगवान बुद्ध पर विशेष आवरण जारी किया जाएगा। भगवान बुद्ध का परिवार कपिलवस्तु में था। भगवान बुद्ध के चातुर्मास सहित छह प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में हैं। उस समय पैसे की क्या कीमत थी उसको भी जोड़ने का प्रयास

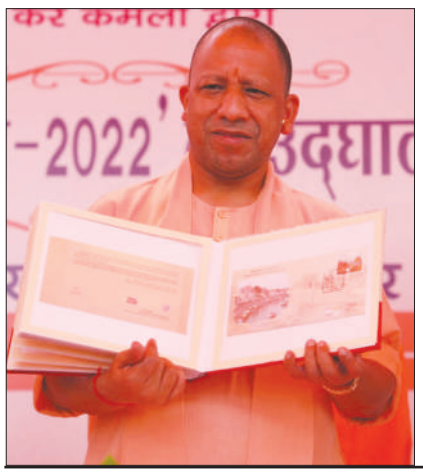

है। उत्तर प्रदेश बहुत समृद्ध है। यहां अपार संभावनाएं हैं। इसलिए प्रदेश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपने प्रदेश की शोभा बढ़ाए। साथ ही समाज में परिवर्तन लाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डाक टिकट का संग्रह एक समय लोगों का शौक हुआ करता था। इसके बिना जीवन अधूरा समझा जाता था। किसी के घर में कोई ऐसा नहीं था जो डाक से न जुड़ा हो। डाक टिकट से वर्तमान को अतीत से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। डाक टिकट एक इतिहास को समेटे रहता है।

11 शहरों में जल्द शुरू होंगी सस्ती घरेलू उड़ान

लखनऊ। पीएम मोदी के हवाई चप्पल पहनने वालों या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी कम दूरी वाले क्षेत्र का हवाई जहाज का सफर कराने का बड़ा अभियान चलाया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत छोटे शहरों के लिए 19 सीटर के विमान का संचालन करेगी। इसके लिए हरियाणा की विमानन कंपनी चयनित की गई है। उत्तर प्रदेश में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जल्द ही प्रदेश के 11 शहरों से सस्ती घरेलू उड़ान शुरू होने जा रही है। इस बार इस योजना के तहत 72 सीटर विमान के बजाय 19 सीटर छोटे विमान उड़ान भरेंगे।

अक्टूबर भर रहेगा खुशनुमा मौसम, खिलने लगी धूप

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बदलते मौसम का असर अब यूपी में दिखने लगा है। लखनऊ से लेकर यूपी के कई जिलों में मौसम में बदलाव जारी है। मानसून के लौटने और सर्दी के आगमन की आहट अब साफ दिखाई दे रही है। सुबह सुबह आसमान में धुंध का असर भी अब दिखने लगा है। कई जिलों में कोहरा भी पड़ने लगा है। वहीं दिन में धूप निकलने के कारण उमस जैसी स्थिति बन रही है।

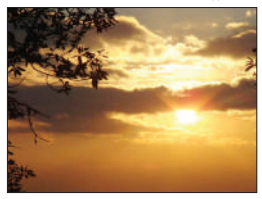

» राजधानी सहित कई जिलों में आसमान साफ रहने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार 18 अक्टूबर तक प्रदेश भर में मौसम सामान्य रहेगा। तापमान में भी एक से दो डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। तीन से चार दिनों तक झमाझम बारिश के बाद लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश से राहत मिल गई है। वहीं प्रदेश के कई जिले ऐसे भी हैं जहां धुंध और कोहरे के बीच दिन की शुरुआत हो रही है। इनमें लखनऊ, कानपुर सहित पश्चिमी यूपी के कई जिले शामिल रहे। आंचलिक मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि अक्टूबर भर मौसम खुशनुमा बना रहेगा। बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि हवाओं के चलते अधिक गर्मी भी नहीं होगी। कल राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ।

अध्यक्ष कोई भी हो, गांधी परिवार को नहीं कर सकते नजरअंदाज : थरूर

» सभी को साथ लेकर चलने की वकालत की

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को मतदान होगा। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। शशि थरूर ने कहा कि अगर वह कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वह सभी को साथ लेकर चलेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार को पार्टी के मामलों से दूर नहीं रखा जा सकता है।

भोपाल में एक पीसी में शशि थरूर ने कहा कि मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले स्वागत से वह खुश हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अन्य राज्यों में ऐसा स्वागत नहीं मिला था। शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अपने रिश्तों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि खड़गे के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कांग्रेस

अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद भी हम पहले की तरह साथ काम करने जा रहे हैं। शशि थरूर ने आगे कहा कि अगर वह अगर वह कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वह सभी को साथ लेकर चलेंगे। साथ ही उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि कोई भी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के परिवार को पार्टी मामलों से दूर नहीं रख सकता है। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए स्वागत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मुझे जो स्वागत मिला उससे मैं खुश हूं।

मैनपुरी सीट पर होगा छह महीने में उपचुनाव

» मुलायम के निधन के बाद अब अखिलेश के कंधों पर जिम्मेदारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के लिए पिछले नौ लोकसभा चुनाव में अभेद्य दुर्ग रही मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी अब पार्टी अध्यक्ष अखिलेश के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। मुलायम के न रहने पर अखिलेश को पार्टी के साथ ही परिवार को भी साधना है। शिवपाल के अभी तक जो तेवर रहे हैं उसे देख अखिलेश को सावधानी से निर्णय लेना होगा। टिकट देने में जरा सी चूक से पार्टी को यहां बड़ा झटका लग सकता है।

सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब मैनपुरी सीट रिक्त हो गई है। यहां छह महीने के अंदर उपचुनाव होना है। वर्ष 1996 से लगातार सात लोकसभा चुनाव व दो उपचुनाव में यहां सपा की साइकिल खूब दौड़ी। वर्ष 2004

में जब मुलायम सिंह ने मैनपुरी सीट से इस्तीफा दिया, उस समय उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव ही यहां से जीते थे। इसी तरह वर्ष 2014 में जब मुलायम ने फिर यह सीट छोड़ी तो उस समय उपचुनाव में उनके पौत्र तेज प्रताप सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इस कारण धर्मेंद्र व तेज प्रताप दोनों का दावा इस सीट पर मजबूत है। वहीं शिवपाल यादव भी पहले कह चुके हैं यदि नेताजी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वे चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि अब मुलायम के न रहने पर स्थितियां बदली हैं। मुलायम ने जब 1996 में जसवंतनगर विधानसभा सीट छोड़ी थी तब से शिवपाल ही इस सीट से चुनाव लड़कर विधायक बनते आ रहे हैं। सैफई के इस यादव परिवार में शिवपाल ही ऐसे व्यक्ति हैं जो मुलायम की तरह सभी दलों में संबंध रखते हैं। इसका फायदा दिल्ली की राजनीति में अखिलेश व पार्टी को मिल सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए अखिलेश भी अपने चाचा से रिश्ते सुधारने के लिए उन्हें मैनपुरी से उतार सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो शिवपाल जसवंतनगर सीट से अपने बेटे आदित्य को चुनाव लड़वा सकते हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश ने चाचा की पार्टी को साथ लिया था, हालांकि उन्हें केवल एक सीट दी थी। अखिलेश ने जब सपा विधायकों की बैठक बुलाई थी उसमें न बुलाए जाने से चाचा नाराज हो गए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि सपा के साथ समझौता उनकी सबसे बड़ी भूल थी।

नीतीश-तेजस्वी का राजनीतिक भविष्य बताएगा उपचुनाव

» परिणाम का संदेश और संकेत राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा

» भाजपा का राजद-जदयू गठबंधन से सीधा मुकाबला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। बिहार, यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत छह राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर तीन नवंबर को उपचुनाव है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सबसे बड़ी लड़ाई बिहार और महाराष्ट्र में होने जा रही है। बिहार में भाजपा को जिन परिस्थितियों में सत्ता से बाहर होना पड़ा, महाराष्ट्र में लगभग उन्हीं परिस्थितियों में वह सत्ता में आई है। बिहार में दो सीटों पर चुनाव है।

बिहार और महाराष्ट्र में भाजपा का राजद-जदयू गठबंधन से सीधा मुकाबला है। सामने नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव की जोड़ी है। महाराष्ट्र में भाजपा

की सहयोगी की भूमिका में एकनाथ शिंदे की पार्टी (बाला साहेब की शिवसेना) है। मतदाताओं का निर्णय चाहे जिसके पक्ष में जाए, परंतु परिणाम का संदेश और संकेत देश भर में जाएगा। बिहार में भाजपा से अलग होकर राजद-कांग्रेस समेत सात दलों की सरकार बनाने वाले नीतीश एवं तेजस्वी का पहली बार चुनाव से वास्ता पड़ा है। राजद के बाहुबली नेता अनंत सिंह के सजायाफ्ता होने से खाली मोकामा सीट पर राजद ने उनकी पत्नी नीलम देवी को प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह गोपालगंज सीट पर भाजपा 2005 से लगातार जीतते आ रही है। पूर्व मंत्री सुबाष सिंह के निधन के बाद भाजपा ने उनकी पत्नी कुसुम देवी को प्रत्याशी बनाया है। राजद की तरफ से मोहन गुप्ता हैं। प्रतिष्ठा की लड़ाई है। भाजपा जीतती है तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए मनोबल बढ़ेगा। जदयू के छिटकने के बाद बिहार में अकेली पड़ी भाजपा के प्रति छोटे दलों का आकर्षण बढ़ सकता है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास), मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) अभी किसी गठबंधन के साथ नहीं हैं।

बलरामपुर अस्पताल में टिटनेस का इंजेक्शन नहीं, मरीज परेशान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

» मरीज बाहर से लाकर लगवा रहे चिकित्सक से इंजेक्शन

लखनऊ। बलरामपुर अस्पताल में इन दिनों टिटनेस का इंजेक्शन नहीं है। नतीजा यह है कि यहां से मरीजों को लौटाया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग बाहर से खरीद कर ला रहे तो उन्हें इंजेक्शन चिकित्सकों द्वारा लगाया जा रहा है। चिकित्सक भी बिना शर्त मान मनौव्वल के बाद इंजेक्शन लगाते हैं।

शनिवार को भी कई मरीज इंजेक्शन के लिए भटक रहे थे। सड़क दुर्घटना और मारपीट में जख्मी मरीजों को भी बगैर टिटनेस का इंजेक्शन दिए ही इलाज हो रहा। इससे मरीजों में इंफेक्शन का खतरा बना है। यह संकट कई दिनों से बना है। इसे लेकर अस्पताल के लोग सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। अस्पताल प्रशासन द्वारा अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकी। जबकि एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है। इस मामले में अस्पताल प्रशासन के लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह हाल कई दिनों से है। अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हैं।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक **बबिता चतुर्वेदी** के लिए **4पीएम** आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (यूपी) से मुद्रित एवं प्रकाशित। **प्रधान संपादक**- अर्चना दयाल, **संपादक** - संजय शर्मा, **स्थानीय संपादक** - सूर्यकांत त्रिपाठी*, **विधि सलाहकार**: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, **वित्तीय सलाहकार**: संदीप बंसल, **कार्टूनिस्ट**: हसन जैदी, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website**: www.4pm.co.in | **RNI-UPHIN/2015/62233** डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।